



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21052025-263277
CG-MH-E-21052025-263277

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379।
No. 379।

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 20 मई, 2025

अधिसूचना सं. सीओ.डीपीएसएस.बीडी.सं. एस 168/02-01-012/2025-2026.—भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) के साथ धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, तथा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड, 2008 के स्थान पर, रिजर्व बैंक एतद्वारा भुगतान विनियामक बोर्ड विनियमन, 2025(अनुलग्नक) प्रकाशित करता है, जो ऊपर उल्लिखित तिथि से लागू होगा।

विवेक दीप, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./112/2025-26]

अनुलग्नक

भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) के साथ धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

- (1) इन विनियमों को "भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025" कहा जाएगा।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ -

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) से है;
- (ख) 'बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है;
- (ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित भुगतान विनियामक बोर्ड से है;
- (घ) 'केन्द्रीय बोर्ड' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 के अंतर्गत गठित भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल से है;
- (ङ) 'सामान्य विनियम' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत बनाए गए भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 से है;
- (च) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है;

- (2) इसमें प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

3. बोर्ड की संरचना -

- (1) बोर्ड की संरचना अधिनियम की धारा 3 में बताए गए अनुसार होगी।

- (2) भुगतान और निपटान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को बोर्ड अपनी बैठक में स्थायी या तदर्थ अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है और बोर्ड की बैठकों में बैंक का प्रधान कानूनी परामर्शदाता स्थायी अतिथि होगा।

4. अधिनियम की धारा 3 (3) (घ) के अंतर्गत नामित सदस्यों की पात्रता और कार्यकाल -

- (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्यता, निष्ठा और प्रतिष्ठा तथा भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित नहीं किया जाएगा, यदि वह व्यक्ति--

- (क) सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि को सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;
- (ख) संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हो;
- (ग) किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो;
- (घ) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो;
- (ङ) बोर्ड के सदस्य के कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो; या
- (च) किसी अन्य भुगतान प्रणाली के साथ हितविरोधिता है और वह ऐसे विरोध को हल करने में असमर्थ है।

- (2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित बोर्ड का सदस्य, जब तक कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित लोक सेवक न हो, वह चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।

- (3) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित बोर्ड का सदस्य, जब तक कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित लोक सेवक न हो, उप-विनियम (2) के अंतर्गत अपने कार्यकाल

की समाप्ति से पहले किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार को कम से कम छह सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बोर्ड से त्यागपत्र दे सकता है, तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

5. बोर्ड को सहायता - बोर्ड को भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

6. बोर्ड के सदस्यों के लिए आचार संहिता -

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य तथा विनियमन 3 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट स्थायी या तदर्थ आमंत्रित अतिथि अनुसूची के अनुसार एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) निम्नलिखित संहिता का उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों को उनके नैतिक आचरण पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे बैंक और इसकी नीतियों में जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(क) सदस्य अपने पद की निष्ठा, गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे।

(ख) निर्णय के लिए या अन्यथा बोर्ड के समक्ष आने वाले किसी भी मामले के संबंध में सदस्य हितविरोधिता का खुलासा करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट कार्यवाही से स्वयं को अलग कर लेंगे।

(ग) सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर या अनजाने में जानकारी नहीं प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) सदस्य सार्वजनिक पद के अनुरूप ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

(3) प्रत्येक सदस्य को सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में होने वाली सभी हानियों और व्ययों के लिए बैंक द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी, सिवाय उनके जो उसके स्वयं के जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण हुए हों।

7. पद रिक्ति -

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामित सदस्य, यदि अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह पद पर नहीं रह सकेगा।

8. बोर्ड की ओर से अधिकार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा -

बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जैसा कि वह बोर्ड के कार्यों के कुशल प्रशासन के लिए उचित और आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि वह आदेश में निर्दिष्ट करें अपनी कोई या सभी अधिकार या कार्य बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य या बोर्ड की उप-समिति या बैंक के अधिकारी(यों) को सौंप सकता है। बशर्ते कि भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड¹ द्वारा पहले से अनुमोदित कोई भी प्रत्यायोजन आदेश इन विनियमों के लागू होने के बाद भी वैध बना रहेगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।

9. बोर्ड की बैठकें और कोरम -

(1) बोर्ड की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे स्थान पर या इस तरह से होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।

(2) सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(3) बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे और उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, शामिल होंगे तथा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के तहत नामित एक सदस्य शामिल होंगे।

(4) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, द्वारा की जाएगी।

(5) बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।

¹ 2017 के वित्त अधिनियम, की धारा 152 द्वारा अंतःस्थापित (9-05-2025 से प्रभावी)।

(6) बोर्ड की किसी बैठक के दौरान अनुमोदन के लिए आने वाले सभी मामलों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(7) यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो कार्य का कोई मद या मुद्दा, जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अपेक्षित है, परिचालन द्वारा सदस्यों को भेजा जाएगा और ऐसे मद पर सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(8) अध्यक्ष, बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर, ऐसे स्थान पर या इस तरह से बोर्ड की बैठक बुलाएगा जैसा वह तय करे।

(9) बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय रहेगी।

10. समितियों का गठन –

(1) बोर्ड अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए समिति (समितियाँ) का गठन कर सकता है, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझा जाए।

(2) समिति को भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित अतिथि के रूप में उस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

11. सदस्यों या आमंत्रितों को देय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते –

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ब) के अधीन बोर्ड में नामित सदस्य, विनियम 10 के उपविनियम (1) के अधीन किसी समिति में नामित सदस्य, तथा बोर्ड या किसी समिति में आमंत्रित प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक तथा यात्रा, परिवहन, आवास और भोजन से संबंधित व्यय के हकदार होंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।

अनुसूची

(विनियम 6 के तहत)

निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा का प्रारूप

मैं, बोर्ड का सदस्य बनने पर या स्थायी या तदर्थ आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी और मैं अपने पद की गरिमा और गोपनीयता को बनाए रखूँगा/रखूँगी तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेरे संज्ञान में आने वाली किसी भी बात या जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित या प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी, सिवाय इसके कि जब इन विनियमों या कानून द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक या अधिकृत किया गया हो।

(हस्ताक्षर)

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th May, 2025

Notification No. CO.DPSS.BD.No.S168 /02-01-012/2025-2026.—In pursuance of sub-section (4) of section 3 read with sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), and in supersession of the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, the Reserve Bank hereby publishes the annexed Payments Regulatory Board Regulations, 2025 which shall come into force from the date mentioned above.

VIVEK DEEP, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./112/2025-26]

ANNEX

Payments Regulatory Board Regulations, 2025

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 read with sub-sections (1) and (2) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank of India hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement –

- (1) These Regulations may be called the “Payments Regulatory Board Regulations, 2025”.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions –

- (1) In these regulations, unless, the context otherwise requires –

- (a) 'Act' means the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);
- (b) 'Bank' means the Reserve Bank of India constituted by the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (c) 'Board' means the Payments Regulatory Board constituted under sub-section (2) of Section 3 of the Act;
- (d) 'Central Board' means the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India constituted under Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (e) 'General Regulations' means the Reserve Bank of India General Regulations, 1949 made under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (f) 'Member' means a member of the Board;

- (2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Composition of Board –

- (1) The composition of the Board shall be as specified in section 3 of the Act.

- (2) The Board may invite persons with experience in the fields of payment and settlement systems, information technology, law, etc., to attend its meeting either as permanent or as *ad hoc* invitees and the Principal Legal Adviser of the Bank shall be a permanent invitee to the meetings of the Board.

4. Eligibility and Tenure of members nominated under section 3 (3) (d) of the Act –

- (1) The Members of the Board referred to in clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act shall be nominated from amongst persons of ability, integrity and standing, having knowledge, experience and expertise in the field of payment systems, information technology including cyber security, law, etc., by the Central Government:

Provided that no person shall be nominated as a Member, in case such person—

- (a) has completed the age of seventy years on the date of appointment as Member;
- (b) is a Member of Parliament or any State Legislature;
- (c) has been at any time, adjudged as an insolvent;
- (d) has been convicted of an offence which is punishable with an imprisonment for a term of one hundred and eighty days or more;
- (e) is physically or mentally incapable of discharging the duties of a Member of the Board; or
- (f) has a material conflict of interest with any other payment system and is unable to resolve such conflict.

- (2) A Member of the Board nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act, unless he is a public servant as defined in sub-section 28 of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, shall hold office for a period of four years and shall not be eligible for re-nomination.

- (3) A Member of the Board nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act, unless he is a public servant as defined in sub-section 28 of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, may resign from the Board, at any time before the expiry of his tenure under sub-regulation (2), by giving to the Central Government, a written notice of not less than six weeks, and on the acceptance of the resignation by the Central Government, he shall cease to be a Member of the Board.

5. Assistance to the Board –

The Board shall be assisted by the Department of Payment and Settlement Systems (DPSS), Reserve Bank of India which shall report to the Board.

6. Code of Conduct for Board Members –

(1) Every Member, referred to in sub-section (3) of section 3 of the Act, and permanent or *ad hoc* invitee, referred to in sub-regulation (2) of regulation 3, of the Board shall sign a declaration as per the Schedule.

(2) The following code aims at providing broad guidance to Members of the Board on their ethical conduct, which shall help enhance public trust and confidence in the Bank and its policies.

- (a) Members shall act in a manner consistent with the integrity, dignity and reputation of their office.
- (b) Members shall disclose any conflict of interest with regard to any matter that comes up for decision or otherwise to the Board and, if necessary, recuse themselves from the specific proceedings.
- (c) Members shall ensure that all information received by them as a Member of the Board shall be kept confidential and shall not be revealed to any person either knowingly or unknowingly.
- (d) Members shall maintain the highest standards of probity, consistent with public office.

(3) Every Member shall be indemnified by the Bank against all losses and expenses incurred in discharging assigned duties, except such as may happen from his/her own willful act or default.

7. Vacation of Office –

A Member nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act shall cease to hold office if he absents himself without the leave of the Chairperson from three consecutive meetings of the Board.

8. Powers on behalf of the Board by whom to be exercised –

The Board may, by general or special order, delegate any or all its powers or functions to the Chairperson or a Member of the Board or a Sub-Committee of the Board or officer(s) of the Bank as it may deem fit and necessary for the efficient administration of the functions of the Board, subject to such conditions and limitations, if any, as it may specify in the order.

Provided that any order of delegation previously approved by the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems¹ shall continue to be valid even after these Regulations come into force unless amended or rescinded by the Board.

9. Meetings of the Board and Quorum –

(1) The Board shall ordinarily meet at least twice in a year at such place or through such mode as may be decided by the Chairperson from time to time.

(2) Members shall be given sufficient notice to enable them to attend the meetings.

(3) The quorum for holding a meeting of the Board shall be three Members and shall include the Chairperson and in his absence, the Deputy Governor who is the Member of the Board and a Member nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act.

(4) The meetings of the Board shall be presided over by the Chairperson, and in his absence by the Deputy Governor who is a Member of the Board.

(5) Each Member of the Board shall have one vote.

(6) All matters for approval which come up during any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the Deputy Governor who is a Member of the Board, shall have a second or casting vote.

(7) If the Chairperson so directs, an item of business or issue which requires a decision of the Board, may be referred to Members by circulation and such item may be decided by a majority of votes of Members, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the Deputy Governor who is a Member of the Board, shall have a second or casting vote.

(8) The Chairperson shall, on a request made in writing by any Member of the Board, convene a meeting of the Board at such place or through such mode as he may decide.

1. Subs. by Finance Act 2017, s. 152 (w.e.f 9-05-2025).

(9) The proceeding of the Board shall be confidential.

10. Constitution of Committees –

(1) The Board may constitute Committee(s) for providing assistance or advice in the performance of its functions, as may be considered necessary from time to time.

(2) A Committee shall have the power to invite persons with experience in the field of payment and settlement systems to attend the meetings of that Committee as invitees.

11. Remuneration and other allowances payable to the members or invitees –

Members nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Act to the Board, Members nominated under sub-regulation (1) of regulation 10 to any Committee, and invitees to the Board or any Committee shall be entitled to remuneration for each meeting they attend, and expenses relating to travel, transportation, lodging and boarding, as may be decided by the Board from time to time.

SCHEDULE

(*vide Regulation 6*)

FORM OF DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I, on becoming a member of the Board or being invited as permanent or ad hoc invitee, do solemnly and sincerely declare that I will faithfully perform the duties to the best of my ability and that I will uphold the dignity of the position and that I will observe secrecy and will not directly or indirectly communicate or divulge any of the matters or any information which may come to my knowledge in the discharge of my duties, except when required or authorised to do so by these Regulations or by law.

(Signature)